

(86)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 996-तीन/2009 निगरानी - विरुद्ध आदेश दिनांक
6-7-09 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण
क्रमांक 658/2006-07 अपील

- 1- विधाता पुत्र बोडराम कुशवाह
 - 2- बुद्धी पुत्र जागेश्वरप्रसाद कुशवाह
 - 3- रामवालक 4- रमेश 5- सुरेश
पुत्रगण रामावतार कुशवाह
 - 6- वृन्दा 7- छोटा पुत्रगण मंगल कुशवाहा
 - 8- रामविश्वास 9- रामनिवास पुत्रगण अनंतराम कुशवाह
 - 10- कामता पुत्र खेदू कुशवाह 11- रामबहोर पुत्र तीरथप्रसाद
 - 12- तिलकधारीप्रसाद 13- सिद्धमुनि 14- नीलकण्ठ
पुत्रगण अनुसूईया प्रसाद ब्राहमण
 - 15- कमलेश्वर प्रसाद पुत्र कल्लूराम ब्राहमण
 - 16- काशीप्रसाद 17- रामनिहोर पुत्रगण अनुसूईयाप्रसाद ब्राहमण
- सभी ग्राम पिपरा थाना सेमरिया जिला रीवा

----आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- गंगाप्रसाद 2- भैयालाल 3- रामफल
पुत्रगण पराग कुशवाह
- 4- बुद्धसेन पुत्र रामप्रताप कुशवाह
- 5- जगदीशप्रसाद 6- रामरूप पुत्रगण विशेश्वरप्रसाद कुशवाह
- 7- रामस्वरूप 8- रामनिहार 9- रामजी
पुत्रगण रामसजीवन कुशवाह
- 10- लालजी पुत्र चुनवादी कुशवाह

११- चन्द्रशेखर १२- सुग्रीव १३- अच्छेलाल १४- सूर्यदीन

पुत्रगण बिदुर प्रसाद कुशवाह

१५- रामाधार पुत्र बोडेराम कुशवाह

१६- सोखीलाल १७- जवाहर पुत्रगण रामेश्वर कुशवाह

सभी ग्राम पिपरा थाना सेमरिया जिला रीवा

---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री हरिप्रकाश द्विवेदी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक १५-०९-२०१७ को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक ६५८/२००६-०७ अपील में पारित आदेश दिनांक ६-७-२००९ के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण का सारौंश यह है कि आवेदक क्रमांक १ ने अति.तहसीलदार टप्पा सेमरिया को म०प्र०भू राजस्व संहिता १९५९ की धारा १७८/११० के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पिपरा की भूमि सर्वे क्रमांक ३०८ रकबा १.९८ ए. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) के बटवारे की मांग की। तहसीलदार ने पक्षकारों की सुनवाई कर आदेश दिनांक २४-८-२००० पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि का बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपील प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने वावत् आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक ३०-११-०६ पारित किया तथा लगातार तीन वर्ष तक वारिसान के नाम नहीं बतलाना और न आवेदन देना मानकर अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक ६५८/२००६-०७ अपील में पारित आदेश दिनांक ६-७-२००९ से

अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण गुणदोष के आधार पर निर्णय करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने एक पक्षकार की मृत्यु पर अपील प्रकरण Abate होने से अपील निरस्त की है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 658/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-2009 में विवेचित किया है कि अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किसी एक पक्षकार के मृत होने पर (यदि अन्य पक्षकार मौजूद हों तो) अपील निरस्त नहीं होगी बल्कि मृतक पक्षकार के विरुद्ध अपील उपसमन होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूरी अपील ही निरस्त कर दी है जो विधि एवं प्रक्रिया के तहत किया गया आदेश नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के आदेश दिनांक 30-11-06 एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 6-7-2009 का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा आदेश दिनांक 6-7-09 में निकाला गया निष्कर्ष सही है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 658/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-7-2009 उचित होने से यथावत् रखा जाता है एवं निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस.एस.अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर